



विकास की समझ

आपके विचार में विकास क्या है और उसमें क्या-क्या शामिल किया जाना चाहिए?

विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है क्योंकि अलग-अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग-अलग हैं। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा वे सुखी जीवन जी सकें? इसमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसका हल कैसे निकालें? इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए? इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे।

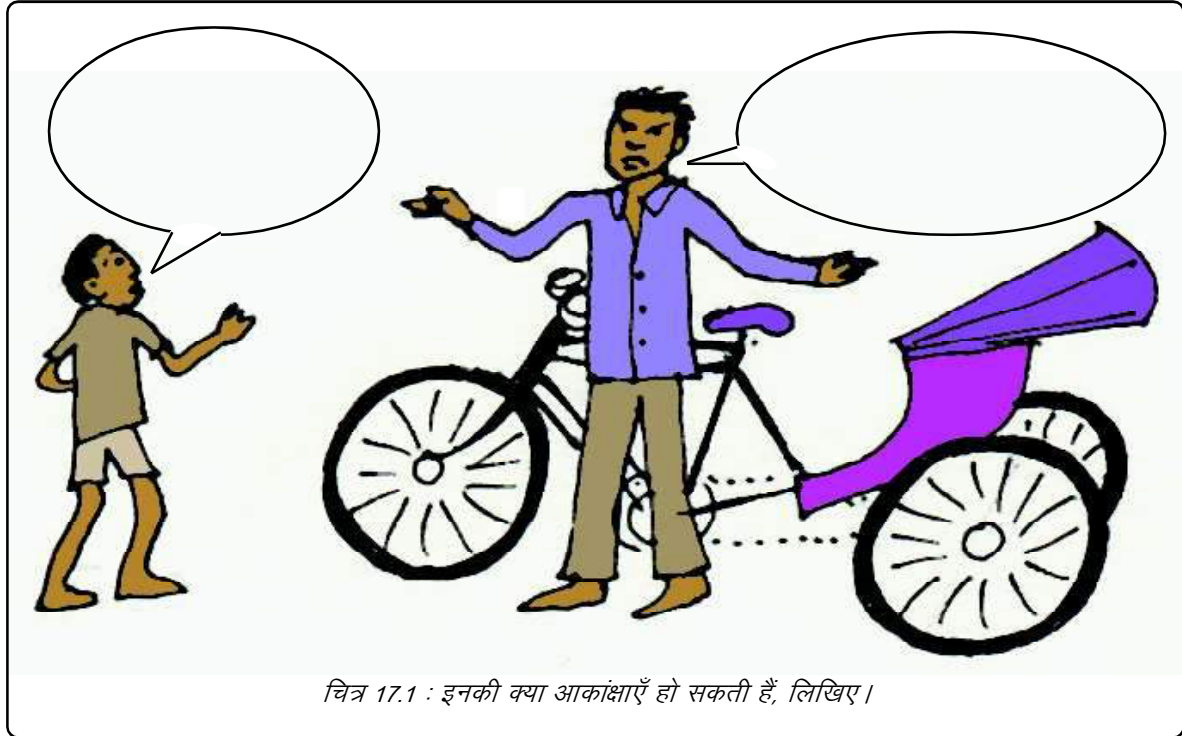
विकास – विभिन्न लोगों की दृष्टि से

नीचे की तालिका में कुछ लोगों की आकांक्षाएँ दर्शायी गई हैं। इनमें वे व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सोचते हैं? की कल्पना की गई है। ये उदाहरण मात्र हैं हो सकता है कि उनके और भी लक्ष्य हों। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावित आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए तालिका को पूर्ण कीजिए –

तालिका – 17.1

क्र.	विभिन्न लोग	विकास के लक्ष्य/आकांक्षाएँ
1.	दिहाड़ी मजदूर	वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए शिक्षा,
2.	उद्योगपति	सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क-बिजली की व्यवस्था, शान्तिपूर्ण वातावरण,
3.	कॉलेज की छात्रा	शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर, लड़कों के समान स्वतंत्रता व सुरक्षा,
4.	एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर	रोजगार के अवसर, आवास की सुविधा,
5.	महिला खेत मजदूर	अच्छी मजदूरी, सुरक्षा, साल भर रोजगार व स्वास्थ्य सेवाएँ

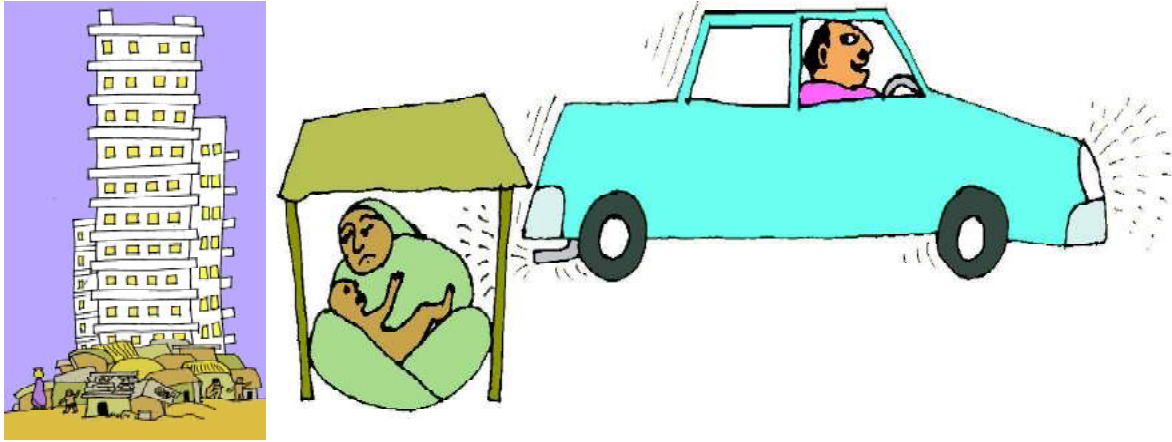
6.	आप स्वयं	-----
7.	छोटा किसान	-----
8.	शिक्षक	-----
9.	गाँव का सरपंच	-----



तालिका 17.1 के निरीक्षण से यह पता चलता है कि प्रायः सभी लोग उन चीजों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आकांक्षाएँ कई तरह की हैं। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोज़गार की सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। वहीं कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है, वहीं दिहाड़ी मज़दूर सम्मानजनक मज़दूरी के साथ साल भर काम मिलने की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मज़दूरी न करना पड़े।

कभी-कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे- एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है। हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसन्द न हो। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है। वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएँ प्राप्त करने की होती है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएँ रखता है। परन्तु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या 'सार्वजनिक हित' की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए- विद्यालयों की स्थापना से गाँव/शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है जो



चित्र 17.2 शीर्षक

पहले नहीं मिल पा रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल हैं जो सबके हितों के लिए होते हैं।

सार्वजनिक हितों को समझने का प्रयास करें। कोई एक गाँव है। उस गाँव में आने-जाने के लिए एक पगडंडी थी। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती परन्तु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील होकर बंद हो जाता था। इस कारण वहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को विचार आया कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दी जाए। उस पगडंडी से लगी हुई ज़मीन के कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने हेतु अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए पर वहीं कुछ और लोगों ने इससे इंकार किया। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई तो अंततः सभी भूस्वामी सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने को तैयार हो गए। इस प्रकार सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाया।

ऊपर दिए गए चित्रों के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें।

आपके गाँव/शहर के लिए कौन-कौन से विकास के लक्ष्य होने चाहिए और क्यों? कुछ उदाहरण देते हुए समझाइए।

विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। चर्चा करें।

आपके यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने एवं सबके लिए उपलब्ध करवाने हेतु तीन सुझाव रखिए।

विकास की योजनाओं में विरोधाभास

क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक है? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें विस्थापन हेतु मजबूर

होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पातीं। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है।

ओडिशा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्कों की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है। इससे वहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है, बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार-बार अपना विरोध दर्ज किया है। उनका तर्क है कि मुआवज़े की राशि खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मज़दूरी के लिए भटकना पड़ता है क्योंकि जमीन के अभाव में उनके पास नियमित रोज़गार नहीं होता। साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित होती है।

पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है जो वहाँ आस पास रहनेवालों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं।

(स्रोत: चर्निंग दी अर्थ – श्रीवास्तव एवं कोठारी, पेंगुइन, 2012)

इस प्रकार के विरोधाभास उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं –

शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है जिससे वहाँ का वातावरण और जल प्रदूषित होता है जबकि बहुत कम खर्च पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है।

सिंचाई हेतु जब बाँध बनाए जाते हैं तो बाँध के निचले इलाके के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं बाँध के ऊपर वाले क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे।

ओडिशा राज्य में उद्योगों की स्थापना से क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है?

आपके मतानुसार सार्वजनिक हित को ध्यान रखते हुए इस उदाहरण में क्या कार्य किया जाना चाहिए?



चित्र 17.3 : उद्योग और उत्खनन

कोई अन्य उदाहरण दें जहाँ इस प्रकार का विरोधाभास पैदा हुआ है?

क्या सार्वजनिक हित के नज़रिए से इनके हल ढूँढे जा सकते हैं? चर्चा करें।

आय एवं अन्य लक्ष्य

आइए हम एक बार पुनः तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। इसमें से अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है, जैसे कि मज़दूर बेहतर मज़दूरी, उद्योगपति अधिक लाभ, कॉलेज की छात्रा एवं बेरोज़गार इंजीनियर रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँगे तथा उनका जीवन स्तर उठेगा। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ-साथ लोगों की और भी इच्छाएँ होती हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं।

तालिका 17.1 के आधार पर बताइए कि लोग आय के अतिरिक्त और किन-किन चीज़ों को अपने लिए आवश्यक मानते हैं –

1.
2.
3.

व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भयमुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसरों की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोजगार के साथ-साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोज़गार में स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध होता है।

आय के मापदंड और आय का वितरण

आइए अब हम चर्चा करें कि देश के लिए कौन-कौन से विकास के सूचक होने चाहिए। देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन से हम समाज के आय का अंदाज़ लगा सकते हैं। इसीलिए हम प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. को एक सूचक मानते हैं। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है।

तालिका – 17.2

चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14	
राज्य	प्रति व्यक्ति आय
महाराष्ट्र	1,14,392 रु.
केरल	1,03,820 रु.
बिहार	31,199 रु.

तालिका 17.2 महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। हम पिछली कक्षा से याद करने की कोशिश करें कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है – उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम। इसका अर्थ है कि औसतन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपए की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध हैं जबकि बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति के लिए केवल 31,199 रुपए की वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध हैं। इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं एवं समय के साथ इनकी प्रगति का अंदाज़ लगा सकते हैं।

प्रति व्यक्ति आय मात्र एक संकेत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों को इतना प्राप्त हो रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग-अलग है। कुछ लोगों की आय औसत से बहुत अधिक होती है किंतु अधिकांश लोगों की आय औसत से कम होती है। इस असमानता को समझने के लिए हमें आय का वितरण भी देखना होगा।

औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है फिर भी यह आय के वितरण की असमानताएँ छुपा देती है। मान लीजिए कि एक समूह में पाँच लोग हैं जिनकी आय अलग-अलग है। हम यह जानना चाहते हैं कि दो वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ है। इसे तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं –

तालिका – 17.3

वर्ष	समूह की औसत आय (रुपए में)						कुल आय	प्रति व्यक्ति आय (औसत आय)
	A	B	C	D	E			
2010	2000	4000	5000	6000	3000	20,000	4000	
2012	2000	8000	6000	6000	8000	30,000	6000	

तालिका 17.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2012 की औसत आय में वृद्धि हुई है अर्थात् इस समूह में विकास दिखाई दे रहा है परन्तु सभी लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ओर B, C और E की आय में वृद्धि हुई है दूसरी ओर A और D की आय स्थिर है। अतः औसत आय को विकास के मापन का सूचक मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के आय के वितरण को भी देखना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि सभी लोगों को विकास का मौका मिला है या यह विकास कुछ लोगों तक ही सीमित है।

इसी प्रकार उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है क्योंकि इससे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। अलग-अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, सरकार इसकी जानकारी सर्वे द्वारा प्राप्त करती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है। जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है, वह आर्थिक रूप से उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता है। उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का पता चलता है।

आइए तालिका 17.4 का अवलोकन करें –

तालिका – 17.4

भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (वर्ष 2011-12)

ग्रामीण समूह	कुल उपभोग व्यय
कृषक	1436 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
वेतनभोगी	2002 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
आकस्मिक खेत मज़दूर	1159 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

स्रोत – एन एस एस ओ रिपोर्ट नं. 562, 2015. सामाजिक-आर्थिक समूहों में परिवार उपभोक्ता व्यय

उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कृषक अपने उपभोग पर कुल 1436 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च करता है। इसी प्रकार ग्रामीण वेतनभोगियों का प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय 2002 रुपए हैं। कृषि क्षेत्र में आकस्मिक मज़दूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1159 रुपए है। इस तरह से इस तालिका के अनुसार आकस्मिक मज़दूरों का कुल उपभोग व्यय सबसे कम है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता है और मज़दूरी की दर भी कम रहती है। इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रखकर किया जाता है तो इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखना चाहिए।

नीचे दिए गए पिरामिड में भारत में आय के आँकड़े दर्शाए गए हैं। इन्हें अपने शब्दों में समझाएँ।



छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2013-14 में 58,547 रुपये थी। इसकी तुलना अन्य राज्यों से करें।

क्या आप अपने परिवार के प्रतिव्यक्ति आय का पता लगा सकते हैं?

आय के असमान वितरण का क्या असर पड़ता है? चर्चा करें।

अपने आसपास के किन्हीं दो भिन्न परिवारों के प्रति माह व्यय का पता करें। इनमें यह अंतर क्यों है, समझाएँ।

विकास के अन्य सूचक : शिक्षा एवं स्वास्थ्य

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है वहाँ बाल मज़दूरी की प्रथा स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है वरन् समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी प्रतिभा का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने के मौके मिलते हैं। समाज में महिलाओं की बात को सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उसकी भूमिका बदलती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है।

मानव विकास सूचकांक

विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है किन्तु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लम्बी हो सकती है पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग दो दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टों में भी विभिन्न देशों की तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है।

जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए।

पाँच वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक

स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण को दो रूपों में मापा जा सकता है उम्र के अनुसार ऊँचाई तथा उम्र के अनुसार वज़न। बच्चों में ऊँचाई तथा वज़न का स्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोषित कहलाएँगे। इस बात की बेहतर जानकारी आप आँगनबाड़ी केन्द्र में जाकर पता कर सकते हैं। उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर हम निम्नांकित तालिका का अवलोकन कर सकते हैं—

तालिका – 17.5

भारत व पड़ोसी देशों के चयनित मानव विकास सूचक (वर्ष 2010)

देश	जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	साक्षरता दर 15+ (प्रतिशत)	5 वर्ष के उम्र के बच्चों में कुपोषण का स्तर	
			उम्र के अनुसार कम ऊँचाई (प्रतिशत)	उम्र के अनुसार कम वज़न (प्रतिशत)
नेपाल	69	59	49	39
भारत	65	63	48	43
चीन	73	98	10	04
श्रीलंका	75	91	17	21

* भारत का साक्षरता दर + 7 वर्ष से निर्धारित होता है

स्रोत – यूनेस्को रिपोर्ट, एचडीआर-2013, यूनिसेफ-2012

मानव विकास की दृष्टि से हमें आय व अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप से देखना चाहिए। इसी नज़रिए से हमने मानव विकास के सूचकों को समझा है। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसके सबसे अहम पहलू हैं।

तालिका 17.5 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

किन देशों में मानव विकास का स्तर बेहतर दिखाई दे रहा है?

पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रतिव्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है जो नेपाल की तुलना में अधिक है। फिर भी मानव विकास सूचकों में बहुत अंतर दिखाई नहीं देता। चर्चा कीजिए।

भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रतिव्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की अलग-अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास 100 डॉलर हैं और वह व्यक्ति भारत आता है तो उसके पास कितने रुपए होंगे? एक डॉलर = 65 रुपए बाज़ार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6,500 रुपए होंगे परन्तु यहाँ हम बाज़ार भाव का उपयोग नहीं करते।

यदि बाज़ार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपए में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है? विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों के आँकड़ों द्वारा यह पता करते हैं कि एक डॉलर में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवा खरीदी

जा सकती है? उपर्युक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 डॉलर खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएँ खरीदता है। जब वह भारत आता है तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे? मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपए खर्च किए। यानी एक डॉलर 35 रुपए के बराबर हुआ। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात से की जाती है ताकि क्रय शक्ति समता (परचेसिंग पॉवर पैरिटी) बनी रहे।

नीचे दी गई तालिका 17.6 पर चर्चा करें –

देश	प्रति व्यक्ति आय (अमेरिकी डॉलर में)
भारत	5497
नेपाल	2311
श्रीलंका	9779
चीन	12547

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2015

क्रय शक्ति समता के आधार पर तुलना बेहतर क्यों है? इस तालिका को देखते हुए भारत और चीन की तुलना कीजिए।

सार्वजनिक सुविधाएँ

केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएँ नहीं खरीद सकते जैसे, अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक-पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते परन्तु एक सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारु व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएँ कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे कुपोषण का स्तर कम होता है।

मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लम्बे समय तक कैसे रहता है इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। 1991 में यहाँ के केवल 64 प्रतिशत लोग साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था हालाँकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे।

राज्य सरकार ने पाठशालाएँ शुरू कीं और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे-धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय तथा पीने के पानी आदि की सुविधाएँ दी गईं। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक-बालिका की शिक्षा पर औसत 1049 रुपए खर्च किए जा रहे थे जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2005 रुपए था। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। यहाँ की महिलाएँ कामकाजी एवं आत्मविश्वासी हैं,

खुद भी घर से बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती हैं। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी है। इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफी बदलाव ला दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.98 प्रतिशत तक पहुँच गई है। अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफी बेहतर है।

इसकी एक झलक नीचे दी गई तालिका 17.7 में देख सकते हैं –

हिमाचल प्रदेश में पाँच वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा पाने वाले छात्र-छात्राएँ

	1993 (प्रतिशत में)	2006 (प्रतिशत में)
छात्राएँ	39%	60%
छात्र	57%	75%

(स्रोत: अ. डे. प्रोब – रीविजिटेड, ओ यू पी, 2011)

इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं। इन मापदंडों के आधार पर मानव विकास संकेतकों में हुई प्रगति का जब हम अनुमान लगाते हैं तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर जैसे मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है।



अभ्यास

- सही विकल्प चुनिए –
 - मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति औसत आय 4 हजार रुपए है। यदि अगले दो वर्षों में इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति औसत आय 5 हजार हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि –
 - समूह का स्तर घटा है।
 - सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है।
 - समूह का स्तर बेहतर हुआ है।
 - सभी व्यक्तियों की आय घटी है।
 - सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है –
 - अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए।
 - पैसे कमाने के लिए।
 - सार्वजनिक हित के लिए।
 - सरकारी कार्यालयों के लिए।

2. विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन-कौन से हैं?
3. भारत की प्रतिव्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है?
4. भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है? एक लेख लिखिए।
5. आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास परियोजनाओं में क्या संभावनाएँ दिखती हैं? क्या कोई विरोधाभास दिखाई देता है, संक्षिप्त में समझाइए।
6. अलग-अलग समूह के कुल उपभोग व्यय से हमें क्या पता चलता है? क्या यह महत्वपूर्ण संकेतक है?
7. महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या-क्या उपाय करना चाहिए? अपने विचार लिखिए।
8. तालिका 17.3 में हम मानकर चल रहे हैं कि इस दौरान वस्तु और सेवा के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चर्चा करें।
9. औसत आय से आय के वितरण की असमानताएँ छिप जाती हैं? समझाएँ।
10. ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा।
11. इस पाठ में दिए गए संकेतों के अतिरिक्त विकास के लिए और क्या संकेतक हो सकते हैं?
12. निम्नलिखित विचारों पर चर्चा करें—
 1. शिशु मृत्यु दर
 2. बीमारी पर खर्च किया गया व्यय
 3. स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत
 4. वर्ष भर में छह महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत
13. यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हों (परीक्षाफल के अतिरिक्त) तो उसमें आप क्या-क्या रखना चाहेंगे। अपने विचार लिखिए।